परियोजना के निर्माण-कार्य उतनी धनराशि के अनुसार अब किए जा रहे हैं जितनी व्यवस्था राज्य सरकार वार्षिक योजनाओं में इस परियोजना के लिए कर सकी है।

1984-85 के लिए योजनागत विचार-विमर्शों के दौरान राज्य सरकार द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तारीख 1990 है।

शहरों का विकास

3667. **श्री कमला मिश्र मधुकर**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश के कुछ चुने हुए शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्व चम्पारन के जिला मुख्यालय मोतीहारी को, जहां पर दुर्लभ प्राकृतिक सौन्दर्य है, इस वर्ष इस योजना में शामिल करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खेल विभाग में तथा निर्माण और आवास मंत्रालय से और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की परियोजना के अधीन।

(ख) और (ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह सच है कि नगर का प्राकृतिक सौन्दर्य है तथा नगर के बीच में एक बड़ी मोती झील है जो कि उचित ढंग से विकास करने पर पर्यटक स्थल बन सकती है। बिहार सरकार से आगे यह पता चला है कि योजनाएं पहले ही राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण

3668. **श्री कमला मिश्र मधुकर**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत एक वर्ष के दौरान भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण संबंधी योजना के अन्तर्गत बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में भूमिहीन श्रमिकों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

(ख) क्या इन सभी मकानों का निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टाओं के अनुसार किया गया है और क्या उनकी नमूना जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ हैं तथा ठेकेदारों ने खूब पैसा बनाया है ?

खेल विभाग में तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय होने के कारण, सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। निर्माण और आवास मंत्रालय भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना जो संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में है, का प्रबोधन करता है। बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में पिछले एक साल के दौरान भूमिहीन श्रमिकों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

Reclamation of Land in Bombay

3669. **SHRI R.R. BHOLE** : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state ;